

मो. ईकराम खान और पुत्रगण

बनाम

व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

21 जुलाई, 2004

[न्यायमूर्ति एस.एन. वरियाव और न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत]

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948:

धारा 2(एच)-विक्रय—वारंटी समझौते के तहत एजेंट द्वारा ग्राहकों को मोटर पुर्जों की आपूर्ति—एजेंट द्वारा निर्माता से पुर्जों की ऐसी आपूर्ति पर प्राप्त राशि—कर निर्धारण—अभिनिर्धारित, निर्धारिती ने ग्राहकों को आपूर्ति किए गए पुर्जों के लिए मूल्य का भुगतान प्राप्त किया—संव्यवहार कर के अधीन थे।

महाराष्ट्र में वाहनों के एक निर्माता ने वारंटी अवधि के दौरान दोषपूर्ण पुर्जों को बदलने के लिए अपने ग्राहकों के साथ एक समझौता किया था। उत्तर प्रदेश राज्य में एजेंट वारंटी समझौते के तहत ग्राहकों को पुर्जों की आपूर्ति करता था और निर्माता से इसकी कीमत प्राप्त करता था। मूल्यांकन प्राधिकरण ने राय दी कि लेन-देन विक्रय के बराबर था और मूल्यांकन किया कि एजेंट द्वारा निर्माता से प्राप्त राशि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के तहत कर के लिए उत्तरदायी है। आयुक्त (अपील) ने

मूल्यांकन को बरकरार रखा। लेकिन व्यापार कर न्यायाधिकरण ने माना कि कोई विक्रय नहीं हुआ था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि लेन-देन को कर के अधीन करने के लिए विक्रय माना था। निर्धारिती-अभिकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने यह सही धारित किया था कि संव्यवहार कर के अधीन था। उच्च न्यायालय और कर प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से लेखबद्ध किया गया तथ्यात्मक निष्कर्ष यह है कि निर्धारिती ग्राहकों को आपूर्ति किए गए पुर्जों के मूल्य का भुगतान प्राप्त कर लिया है। निर्माता द्वारा खुले बाजार से दोषपूर्ण भागों के प्रतिस्थापन के उद्देश्य से पुर्जे क्रय किए गए ऐसे संव्यवहार के लिए उसने कर का भुगतान किया होगा। स्थिति अलग नहीं है क्योंकि निर्धारिती ने पुर्जों की आपूर्ति की थी और कीमत प्राप्त की थी। मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों ने मो. ईकराम खान और पुत्रगण बनाम व्यापार कर आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ स्पष्ट रूप से एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि लेन-देन प्रकृति में अंतर-राज्य है। [120-ए-डी]

प्रीमियर ऑटोमोबाइलस लिमिटेड और अन्य आदि बनाम भारत संघ, [1972] 2 एस.सी.आर. 526 और विक्रय कर आयुक्त, दिल्ली प्रशासन,

विकास भवन, नई दिल्ली बनाम प्रेम नाथ मोटर्स (पी) लिमिटेड, (1979)
43 एसटीसी 52, विशिष्ट।

प्रेम मोटर्स बनाम विक्रय कर आयुक्त, मध्य प्रदेश, (1986) 61
एससीटी 244 और जियो मोटर्स बनाम केरल राज्य, (2001) 122 एसटीसी
285, उलट दिया गया।

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं. 9618/2003

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के टी.टी.आर. संख्या 332/2201 में दिए
गए निर्णय और आदेश दिनांकित 25.4.2003 आदेश से।

के साथ

सी.ए. संख्या 9619/2003

अपीलार्थी की ओर से ध्रुव अग्रवाल और प्रीवीन कुमार।

प्रत्यर्थी की ओर से दत्त त्यागी।

इस न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अरिजीत पासायत द्वारा दिया
गया।

निर्णय (सीए नंबर 9619/2003 के साथ) अरिजीत पसायत, जे.

ये दोनों अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल
न्यायाधीश द्वारा दिए गए एक सामान्य निर्णय से संबंधित हैं। अपीलकर्ता
(इसके बाद 'निर्धारिती' के रूप में संदर्भित) प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों यानी

1990-91 और 1996-97 के लिए उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत पंजीकृत डीलर था। इन अपीलों में एकमात्र सवाल यह है कि क्या वारंटी समझौते के एक हिस्से के रूप में ग्राहकों को पुर्जों की आपूर्ति के लिए निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि कर के लिए उत्तरदायी थी। निर्धारिती मेसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा (इसके बाद 'निर्माता' के रूप में संदर्भित) का एजेंट मो. ईकराम खान और पुत्रगण बनाम व्यापार कर आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ था। निर्माता ने वारंटी अवधि के दौरान दोषपूर्ण पुर्जों को बदलने के लिए वाहनों के खरीदारों (बाद में 'ग्राहकों' के रूप में संदर्भित) के साथ वारंटी समझौता किया था। जैसा कि कर अधिकारियों और उच्च न्यायालय ने पाया, निर्माता ने निश्चित कीमत के लिए भुगतान किया क्योंकि पुर्जों की आपूर्ति करदाता द्वारा ग्राहकों को की गई थी। ग्राहकों को आपूर्ति किए गए पार्ट्स की कीमत के संबंध में निर्माता द्वारा निर्धारिती को क्रेडिट नोट जारी किए गए थे। मूल्यांकन अधिकारी का विचार था कि क्रेडिट नोट्स के माध्यम से प्राप्त भुगतान अधिनियम की धारा 2 (एच) के संदर्भ में विक्रय के बराबर है। कहा गया प्रावधान, जहां तक प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

"(एच) विक्रय अपनी व्याकरणिक विविधताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ, नकदी के लिए माल में संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण (बंधक, आडमान, शुल्क या गिरवी के अलावा) का

मतलब है या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल
और इसमें शामिल हैं-"

तदनुसार, प्रश्न में दो मूल्यांकन वर्षों के लिए कर लगाया गया था। मूल्यांकन के आदेशों पर आयुक्त (अपील), वाराणसी के समक्ष सवाल उठाए गए, जिन्होंने सामान्य आदेश दिनांक 20.6.2001 द्वारा मूल्यांकन को बरकरार रखा। इस मामले को निर्धारिती द्वारा व्यापार कर न्यायाधिकरण, वाराणसी (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') के समक्ष अपील में लाया गया था, जिसने विभिन्न उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया और माना कि कोई बिक्री नहीं हुई थी। मामले को राजस्व द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण में रखा गया था। उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया और माना कि लेनदेन कर की वसूली को आकर्षित करने वाली बिक्री है।

अपील के समर्थन में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कानून में स्थिति अब एकीकृत नहीं है। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड और अन्य आदि बनाम भारत संघ (1972 (2) एससीआर 526) में यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि वारंटी अवधि के दौरान दोषपूर्ण पुर्जों के प्रतिस्थापन में कोई बिक्री शामिल नहीं होगी। विक्रय कर आयुक्त, दिल्ली प्रशासन, विकास भवन, नई दिल्ली बनाम प्रेम नाथ मोटर्स (पी.) लिमिटेड (1979(43) एसटीसी 52) मामले में रिपोर्ट किए गए दिल्ली, मध्य प्रदेश और केरल

उच्च न्यायालयों के फैसलों का भी सहारा लिया गया था। प्रेम मोटर्स बनाम विक्रय कर आयुक्त, मध्य प्रदेश (1986(61) एसटीसी 244) और जियो मोटर्स बनाम केरल राज्य(2001 (122) एसटीसी 285)। यह मो. ईकराम खान और पुत्रगण बनाम व्यापार कर आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ प्रस्तुत किया गया कि निर्धारिती ने, वारंटी समझौते के हिस्से के रूप में, दोषपूर्ण पुर्जों को बदल दिया। इसके लिए एक संविदात्मक दायित्व था और इसलिए, इसमें कोई बिक्री शामिल नहीं थी।

जवाब में, राजस्व के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निर्धारिती और निर्माता के बीच लेनदेन एक अलग लेनदेन था। यह निर्धारिती का मामला नहीं है कि निर्माता ने ग्राहकों को सामान की आपूर्ति की थी। यदि उसने निर्धारिती के माध्यम से ग्राहकों को पुर्जों की आपूर्ति की होती तो स्थिति भिन्न हो सकती थी। निर्माता प्रतिस्थापन करने के लिए बाध्य था। यदि उसके पास संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए पुर्जे नहीं थे, तो उसने पुर्जों के किसी भी विक्रेता से पुर्जे खरीदे होंगे और बिक्री कर का भुगतान किया होगा। वर्तमान मामले में, निर्धारिती ने उस सामान की आपूर्ति की थी जिसके लिए उसे क्रेडिट नोट्स और/या भुगतान के अन्य तरीके के माध्यम से प्रतिफल प्राप्त हुआ था। ऐसी स्थिति होने पर, लेन-देन की कर योग्यता के बारे में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण उचित था।

प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स मामले (सुप्रा) में निर्णय वास्तव में निर्धारिती के लिए कोई सहायक नहीं है। दरअसल वहां स्थिति अलग थी उक्त मामले में मुद्दे अलग थे। मुद्दों में से एक यह था कि क्या पूर्व-कार्य लागत की गणना करते समय वारंटी और वैधानिक बोनस के कारण होने वाले खर्चों को बाहर रखा जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा यह माना गया कि निर्माता बेची गई कारों को कवर करने वाली वारंटी प्रदान करते हैं। वारंटी के तहत दोषपूर्ण निर्माण के कारण सभी दोषों को ठीक करना होगा और दोषपूर्ण पुर्जे को निर्माता या उसके डीलर द्वारा निर्दिष्ट अवधि या कार द्वारा तय की गई अवधि के भीतर मुफ्त में बदलना होगा। जहां तक आपूर्ति किए गए घटकों का संबंध है, कार निर्माता वारंटी प्रदान करने वाले घटकों के निर्माताओं के साथ एक समझौता करते हैं। वारंटी के पीछे का पूरा उद्देश्य यह है कि जिस उपभोक्ता को वाहन के लिए भारी निवेश करना पड़ता है, उसे उचित अवधि के लिए परेशानी मुक्त तरीके से वाहन के उचित प्रदर्शन का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इसलिए, वारंटी की पूरी लागत निर्माता द्वारा वहन की जानी थी। यह मुद्दा मौजूदा मुद्दे से पूरी तरह से अलग था और उक्त मामले में वर्तमान विवाद का कोई जवाब नहीं देता है। प्रेम नाथ का मामला (उपरोक्त), जैसा कि तथ्यात्मक स्थिति से पता चलता है, खरीदार द्वारा भुगतान की गई निश्चित कीमत पर कार की मूल बिक्री के हिस्से के रूप में वारंटी की शर्त के अनुसरण में बदले गए पुर्जों या भागों में संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित है। इस प्रकार तय की गई

और प्राप्त की गई कीमत कार और भागों के लिए एक समेकित मो. ईकराम खान और पुत्रगण बनाम व्यापार कर आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ कीमत थी जिसे वारंटी के अनुसरण में प्रतिस्थापन के माध्यम से आपूर्ति की जानी हो सकती है। वह निर्णय भी वर्तमान विवाद पर कोई प्रकाश नहीं डालता। यद्यपि जियो मोटर के मामले (सुप्रा) और प्रेम मोटर के मामले (सुप्रा) में निर्णय निर्धारिती के रुख का समर्थन करते हैं, हम पाते हैं कि निर्धारिती और निर्माता के बीच लेनदेन की प्रकृति के मूल मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी मामले में निर्माता ने दोषपूर्ण हिस्सों को बदलने के उद्देश्य से खुले बाजार से पुर्जे खरीदे होंगे। ऐसे लेनदेन के लिए, उसे करों का भुगतान करना होगा। स्थिति अलग नहीं है क्योंकि निर्धारिती ने भागों की आपूर्ति की थी और कीमत प्राप्त की थी। अधिकारियों और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गई स्पष्ट तथ्यात्मक खोज यह है कि निर्धारिती को ग्राहकों को आपूर्ति किए गए भागों की कीमत का भुगतान प्राप्त हुआ था। ऐसा होने पर, लेनदेन कर लगाने के अधीन था जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही ठहराया है। जियो मोटर मामले (सुप्रा) और प्रेम मोटर मामले (सुप्रा) में फैसले खारिज किये जाते हैं।

हालाँकि, निर्धारिती के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही तर्कों के लिए यह स्वीकार कर लिया जाए कि लेनदेन पर बिक्री कर लगाया गया था, लेकिन बिक्री की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं

किया गया है, चाहे वह इंटर-स्टेट या अंतर-राज्य हो। यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्माता महाराष्ट्र राज्य में स्थित था और इसलिए, लेनदेन प्रकृति में अंतर-राज्य होगा। हमें नीचे दिए गए अधिकरण के समक्ष निर्धारिती द्वारा दी गई ऐसी कोई याचिका नहीं मिली। इसके विपरीत, मूल्यांकन करने वाले अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दर्ज किया था कि लेनदेन प्रकृति में अंतर-राज्य है। तथ्यात्मक निष्कर्ष के मद्देनजर हमें निर्धारिती की दलील में कोई तथ्य नहीं मिला। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि तथ्यों के आधार पर अन्य मूल्यांकन पर वर्षों के लिए स्थिति भिन्न होगी। हम इस संबंध में कोई राय व्यक्त करना जरूरी नहीं समझते यह निर्धारिती पर निर्भर करता है कि वह अपने रुख के समर्थन में सामग्री रखे, यदि कोई हो, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कानून के अनुसार अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी।

हम अपील खारिज किए जाने का निर्देश देते हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गुंजन गोयल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।